

डिजीटल पत्र

दैनिक



कांग्रेस दर्पण



पटना, 21 जुलाई, रविवार, 2024

बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवादल सदाकृत आश्रम पटना - 10

यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर प्रियंका गांधी का केंद्र पर तंज



संवाददाता | कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। ट्रेनी आईएस पूजा खेड़कर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब यूपीएससी परीक्षा प्रक्रियां को लेकर भी सवाल सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने इसकी प्रक्रिया को लेकर सरकार पर तंज किया और सोशल मीडिया एक्स्पर्स पर पोस्ट करते हुए कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा, यूपीएससी देश की सबसे नामी परीक्षा है और उससे निकले लोग शासन

व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ होते हैं। देश के करोड़ों लोगों का भरोसा और हमारे रोजमरा के शासन-प्रशासन का कामकाज इस संस्था की पेशेवर प्रणाली से जुड़ा है। मैंने खुद देखा है कि इस परीक्षा के लिए युवा कितनी मेहनत, आंखों में ढेर सारे सपने लिए और दिल में लगन के साथ तैयारियां करते हैं। यूपीएससी की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की खबरें बहुत हैरान करने वाली हैं। इस महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में हुई एक भी गड़बड़ी बढ़े सवाल खड़े करती है और लाखों युवाओं के सपनों और उनके

विश्वास पर चोट करती है। जरूरी है कि इन सवालों का जवाब जनता और यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को मिले। क्या इसके लिए यूपीएससी कौन उच्च पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों से आए लोग जिम्मेदार हैं? यदि हाँ तो उन पर कार्रवाई कब? जिस सिस्टम में एक-एक नंबर के चलते उच्च स्तर का कम्पटीशन होता है, उसमें क्या केवल सतही तौर पर जांच करके पल्ला झाड़ना उचित है?

नकली सर्टिफिकेट का सिस्टम एसी, एसटी, ओबीसी, विकलांग व ईडब्ल्यूएस वर्ग के

अभ्यर्थियों को मिलने वाले मौके पर चोट करता है। क्या सर्टिफिकेट जांचने की कोई ठोस संस्थागत प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती? यूपीएससी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व प्रामाणिक बनाने के लिए बदलावों की सख्त जरूरत है, क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यूपीएससी से जुड़े सवाल इस देश के शासन-प्रशासन के प्रति भरोसे और हमारे करोड़ों युवाओं के सपनों से जुड़े सवाल हैं। इस पर सरकार से जवाब आना जरूरी है।



दलित उत्पीड़न के विरोध में सेवा दल यंग बिग्रेड करेगी राजभवन मार्च : आदित्य पासवान

संचारदाता | कांग्रेस दर्पण

बिहार में दलितों और महादलितों पर हो रहे निरंतर उत्पीड़न के विरोध में बिहार कांग्रेस ने अपनी आवाज बुलंद की है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह के पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद तथा सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय यादव के मार्गदर्शन में बिहार प्रदेश सेवादल यंग बिग्रेड 22 जुलाई को दोपहर 1 बजे 'राजभवन मार्च' करेगी। इस मार्च का उद्देश्य राज्य में 65% आरक्षण को फिर से बहाल करना है, जो कि दलित और महादलित समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण मांग है। इसके साथ ही, चौकीदार और दफादार की नियुक्ति को पूर्व की तरह बहाल करने की भी मांग की जाएगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवादल यंग बिग्रेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान ने इस मार्च की घोषणा करते हुए कहा कि इस मार्च का उद्देश्य बिहार की गूँगी-बहरी और भ्रष्ट सरकार को जगाना है। इस राज्य में दलितों और महादलितों पर हो रहे अत्याचार को बर्दाशत नहीं करेंगे और उनकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का हरसंभव प्रयास करेंगे। यह मार्च पटना के राजभवन की ओर अग्रसर होगा, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा होकर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाएंगे।

सेवादल प्रदेश
अध्यक्ष डॉ
संजय यादव ने
कार्यकर्ताओं
से किया
आह्वान,
सफल करें
अभियान
राज्य में 65%
आरक्षण को
फिर से बहाल
करें सरकार



कांग्रेस में शामिल हुए वाल्मीकिनगर के पूर्व रालोसपा प्रत्याशी



संचारदाता | कांग्रेस दर्पण

पटना। वाल्मीकिनगर विधानसभा के रालोसपा के पूर्व प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा अपने हजारों समर्थकों के साथ आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह के समक्ष सदस्यता ग्रहण किए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह ने सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को सदस्यता दिलाने के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी के प्रति उन्होंने निष्ठा

रालोसपा नेता सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा अपने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस हुए में शामिल

प्रदर्शित करते हुए पार्टी में शामिल हुए। उनके आने से पार्टी चंपारण के इलाके में सांगठनिक रूप से मजबूत होगी। कांग्रेस पार्टी के प्रति लगातार प्रदेश में माहौल बना है और सभी पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से

देख रहे हैं। हाल में सभी दलों से लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं ये हमारे नेतृत्व के प्रति आम जनता में विश्वास का ही देन है। सदस्यता लेने के बाद वाल्मीकिनगर पूर्व प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि बिहार सहित

देश में कांग्रेस पार्टी ही एक मात्र विकल्प है जो देश के विकास को समर्पित है और मैं कांग्रेस से जुड़कर खुद को देश के सबसे समर्पित और सच्ची पार्टी के साथ खुद को जोड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सदस्यता समारोह में पूर्व मंत्री कृष्णनाथ पाठक, निर्मल वर्मा, ब्रजेश पांडे, राजेश राठौड़, कपिलदेव प्रसाद यादव, लाल बाबू लाल, डॉ संजय यादव सहित अन्य कांग्रेसजन एवं सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा के हजारों समर्थक उपस्थित रहे।



मुख्यमंत्री ने बिहार को अपराधियों के हवाले कर दिया है: डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह



संगाददाता | कांग्रेस दर्पण

पटना। बिहार में गिरते हुए कानून व्यवस्था और अपराधियों के बढ़े हुए मनसूबे के खिलाफ इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों के साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कांग्रेसजन ने इनकम टैक्स गोलंबर से डाकबंगला चौराहा तक सरकार के विरोध में गगनभेदी नारों के साथ प्रतिरोध मार्च निकाल कर राज्य की एनडीए सरकार को चेतावनी दिया।

इस प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य में अपराधियों का मंसूबा सांतवें आसमान पर पहुंच चुका है। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार को अपराधियों के हाथों गिरवी रख दिया है। दिनदहाड़े किसी भी जिले में अपराध, हत्या, लूट डकैती और बलात्कार की घटनाएं हो जा रही हैं और पुलिस महकमा हाथ पर हाथ धेर बैठी रह रही है। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के हवाले मुख्यमंत्री ने प्रदेश को सौंप दिया है जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। बिहार में जिस तरीके का लॉ एंड ऑफर बना है उसके खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। जिसमें महागठबंधन के सभी साथी मजबूती से सङ्क पर आए हैं। पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि नीतीश कुमार असहाय हो चुके हैं। प्रॉक्सी के तहत इस राज्य में सरकार चलाया जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता को दूर रख अधिकारियों और चार पांच नेताओं द्वारा सरकार संचालित किया जा रहा है।

इस मार्च में शामिल बिहार विधानमंडल दल के नेता डॉ शकील अहमद खान ने कहा कि प्रदेश में आमजन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकार

अपराधियों के हैसलो के आगे
मुख्यमंत्री पस्त:
डॉ अखिलेश
प्रसाद सिंह

बढ़ते अपराध पर
कांग्रेस ने इंडिया
गठबंधन के साथ
निकाला प्रतिरोध
मार्च



के मुखिया अपराध पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं लेकिन इसका अंजाम यह निकल कर आ रहा है कि अपराध और अपराधी उनके नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। प्रदेश की जनता त्रस्त है और अधिकारी और सत्तारूढ़ दल के नेता सत्ता के हनक में अपनी जिम्मेदारियां भूल चुके हैं। बिहार कांग्रेस के मैटिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने बताया कि इंडिया गठबंधन के द्वारा आहूत बिहार के सभी जिलों में प्रतिरोध मार्च निकाला गया है और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने जिला मुख्यालयों में भी प्रतिरोध मार्च निकाला। इस प्रतिरोध मार्च में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ शकील अहमद खान, पूर्व मंत्री कृपानाथ

पाठक, विधायक अफाक आलम, विधान पार्षद, डॉ समीर कुमार सिंह विधायक विजेन्द्र चैधरी, नीतू सिंह, आनन्द शंकर, कोषाध्यक्ष निर्मलेन्दु वर्मा, ब्रजेश पाण्डेय, राजेश राठौड़, लाल बाबू लाल, कपिलदेव प्रसाद यादव, ब्रजेश प्रसाद मुनन, आनन्द माधव शशि रंजन, विनय वर्मा, मनोज कुमार सिंह, अनिल कुमार, शरवतजहां फतिमा गरीब दास, ज्ञान रंजन डाँ० संजय यादव, अलोक हर्ष, प्रभात कुमार सिंह, राजकिशोर सिंह, धनंजय शर्मा, केसर कुमार सिंह गुंजन पटेल, सिद्धार्थ क्षत्रिय, अनुराग चंदन, ललन यादव, रीता सिंह, अखिलेश रसिंह आशुतोष शर्मा अरविन्द लाल रजक, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, शशिकांत

तिवारी, कमलदेव नारायण शुक्ला, उदय शंकर पटेल, संतोष कुमार श्रीवास्तव, वर्षी अख्तर, प्रदुम्न यादव, असफर अहमद, विमलेश तिवारी, मो० कामरान, कुंदन गुप्ता, कैसर अली खान, गुरुजीत सिंह, विशाल ज्ञा, सुदय शर्मा, आदित्य पासवान, धूब कुमार सिंह, फिरोज हसन, मिहिर ज्ञा, आशुतोष त्रिपाठी, हीरा सिंह वगा, मिथलेश शर्मा मधुकर, निधि पाण्डेय, रवि गोल्डन, अब्दुल बाकी, गुरुदयाल सिंह, यशवन्त कुमार चमन, मनीष सिन्हा, ममता निषाद, रूपम यादव, राजेन्द्र चैधरी, मृणाल अनामय, अमित सिकन्दर, राजनन्दन कुमार, सहित हजारों की संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।



विभिन्न धार्मिक एवं अन्य अवसरों पर बिजली काटना गलत परम्परा तथा जनविरोधी

संवाददाता | कांग्रेस दर्पण

आमजन के प्रति जिम्मेदारी निभाने में प्रशासन विफल!

लम्बे समय तक विद्युत वाधित करना उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन!

विभिन्न धार्मिक अवसरों पर (तजिया, मोहम्मद जयंती, दुर्गाजी, सरस्वतीजी आदि के प्रतिमाओं का विसर्जन, रामनवमी, महावीरी अखाड़ा के नाम पर तथा अन्य जुलुस निकालने के नाम पर) प्रशासन तथा बिजली विभाग 12-14 घंटा तक बिजली काटकर अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। यह गलत परंपरा है और जनहीत में नहीं है।

प्रशासन में बैठे अधिकारियों तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों को तनिक भी समझ नहीं है कि भीषण गर्मी के मौसम में लगातार 12-14 घंटे तक बिजली काटने से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग प्रभावित होते हैं। उन्हें पता होनी चाहिये कि उन लाखों लोगों में वृद्धजन हैं, वृद्ध रोगी हैं, बच्चे हैं, बच्चे रोगी



हैं, नवजात शिशु हैं, नवजात शिशु रोगी हैं, महिलाएँ हैं, महिला रोगी हैं, गर्भवती महिलायें हैं, गँवई अस्पतालों में दाखिल रोगी हैं, अन्य कई प्रकार के रोगी हैं, कृषक हैं, छोटे-छोटे व्यवसायी हैं आदि पर बिजली कटने का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है? कितनी तबाही से वे

गुजरते हैं, मरणासन की स्थिति पैदा हो जाती है। बच्चों की पढ़ाई, भोजन बनाने तथा खाने पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? इसका अंदाजा बिजली विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं है।

उनके घर में तो जेनरेटर, इनवर्टर आदि से काम चल जाता है, किन्तु अन्य के घरों में दिया-बाती भी जल रहा है या नहीं, वे नहीं देखते हैं। वे तो बिना सोचे-विचारे अमुक समय से अमुख समय तक बिजली कटने का फटाफट निर्णय ले लते हैं। जनहीत को ध्यान में रखकर निर्णय लेते तो शायद ऐसी समस्या पैदा ही नहीं होती। इतना ही नहीं, बिजली कटने का लाभ अपराधी भी खूब उठाते हैं, मौका मिलते ही हाथ साफ कर लेते हैं।

दशहरा, मोहर्रम, मोहम्मद जयंती, महावीरी अखाड़ा, रामनवमी आदि तथा अन्य अवसरों पर किसी प्रकार का जुलुस निकालने हेतु प्रशासन द्वारा ही लाइसेंस या अनुमति पत्र प्रदान किया जाता है। अनुमति देते वक्त अनुमति पत्र के साथ शर्तनामा भी होनी चाहिये कि जुलुस में शामिल होनेवाले तजिया, विभिन्न प्रकार के मूर्तियों, पंडालों, लाठी-भाला, बाँस-बल्ला आदि का आकार सामान्य होनी चाहिये, बिजली से बचने के

लिये निर्धारित उपायों का पालन करना चाहिये। जुलुस में ज्यादा हुड़दंग नहीं धार्मिक रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं का पालन करते हुए शान्ति मार्च निकालना चाहिये।

जुलुस के देख-रेख, निगरानी और विधि-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, शान्ति समिति के सदस्य आदि रहते ही हैं। सरकारी तंत्र अपनी जिम्मेदारी का अक्षरशः पालन करें और जुलुस में शामिल लोगों से करायें तो बिजली काटने की स्थिति ही नहीं आयेगी। विद्युत विभाग को भी चाहिये कि नयी तकनिक के साथ-साथ बिजली के खम्भों पर कवरयुक्त तार का उपयोग करें। जुलुस निकालने का प्रारम्भिक एवं अन्तिम समय निर्धारित करें।

काश, ऐसा होता!

स्माकान्त सिंह(पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी),
जिरादेई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र,
प्रतिनिधि, बिहार प्रदेश कांग्रेस, पटना,
उपाध्यक्ष व भू—सम्पद प्रभारी,
जिला कांग्रेस कमिटी, सिवान।

इंडिया गठबंधन की ओर से सरकार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया

संवाददाता | कांग्रेस दर्पण

दरभंगा। राज्य की डबल इंजन की सरकार में बढ़ती अपराधिक घटनाएं, गिरती कानून व्यवस्था, लटपाट, झीचार, बेरोजगारी एवं कमरतोड़ महंगाई की लेकर शनिवार को इंडिया गठबंधन की ओर से सरकार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। शनिवार को जिला कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में बलभद्रपुर कांग्रेस कार्यालय से लहेरियासरय समाहरणालय तक प्रतिरोध मार्च करते हुए पहुंचे, जहां पर पहले से मौजूद महागठबंधन के साथीयों के साथ मिलकर लहेरियासरय टावर, लोहिया चौक होते हुए पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पहुंचे। इस मार्च में बिहार विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता व पूर्व मंत्री डॉ. मदन मोहन झा भी सम्मिलित हुए। डॉ. झा ने मीडिया से संबोधित होते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, आए दिन प्रदेश में हत्याएं, लूट पाट, और अपराध की घटनाएं तेज़ी से हो रही हैं जनता में दहशत का माहौल है। वहीं जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, पूर्व मेयर अजय जालान व कांग्रेस प्रवक्ता मो. असलम ने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के लिए शासन-प्रशासन और सरकार ने शामिल भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। प्रतिरोध मार्च में, प्रदेश



प्रतिनिधि मनोज झा, अच्युतानन्द ठाकुर, दयानंद पासवान, रतिकांत झा, उपाध्यक्ष रामपुकार चौधरी, दिनेश गंगनानी, गणेश चौधरी, धनंजय सिंह, देवकीनंदन ठाकुर, राहुल झा, प्रिंस परवेज़,

मो. चांद, सैयद एजाज अनवर, उदितनारायण चौधरी, मो. अंसार हसन, राजा अंसारी, ललन राय, सुनील सिंह, नारायण जी झा, शादाब अतिकी, सैयद तनवीर अनवर, नसीम हैदर,

जयशंकर चौधरी, विशाल महतो, नवीन झा, मो. अंसार, अजय चौधरी, बुच्ची देवी, प्रो. मिथिलेश यादव, बसंत झा, पंकज चौधरी, विवेकानंद चौधरी, राजकुमार पासवान आदि थे।



यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आज केंद्र सरकार पर निशाना साधा

संवाददाता | कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर से संबंधित विवाद के बीच यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रमुख मल्हिकार्जुन खरगे ने शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा-आरएसएस पर भारत के संवैधानिक निकायों के ₹संस्थागत अधिग्रहण में व्यवस्थित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि यूपीएससी को परेशान करने वाले कई घोटाले ₹राष्ट्रीय चिंतार का कारण हैं।

यूपीएससी में हुए कई घोटाले राष्ट्रीय चिंता का कारण: खरगे ने पॉस्ट करते हुए कहा, ₹भाजपा-आरएसएस भारत के संवैधानिक निकायों के संस्थागत अधिग्रहण में व्यवस्थित रूप से शामिल हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, अखंडता और स्वायत्ता को नुकसान पहुंच रहा है। यूपीएससी में हुए कई घोटाले राष्ट्रीय चिंता का कारण हैं। पीएम मोदी और उनके कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री को सफाई देनी चाहिए। जाति और मेडिकल प्रमाणपत्रों में फर्जीवाड़ा करने वाले अयोग्य व्यक्तियों के कई मामलों ने एक 'फुलपूर' सिस्टम को धोखा दिया है।

यूपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे को गुप्त क्यों रखा?: उन्होंने आगे कहा कि यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों सहित लाखों अभ्यर्थियों की वास्तविक आकांक्षाओं का सीधा अपमान है, जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी में रात-दिन कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा, ₹यह बहुत ही निराशाजनक है कि यूपीएससी अध्यक्ष ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पांच साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को एक महीने तक क्यों गुप्त रखा गया? क्या कई घोटालों और इस्तीफे के बीच कोई संबंध है? मोदी जी के इस 'नीली आंखों



वाले रव' को गुजरात से लाया गया और यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में पदोन्तर किया गया।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शासन के हर पहलू को नियंत्रित करने के हताशापूर्ण प्रयास ने इसमें छेद कर दिया है। उन्होंने कहा, ₹सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने सिविल सेवकों को 'भारत का स्टील फेम' कहा था, लेकिन मोदी सरकार के शासन के हर पहलू को नियंत्रित करने के हताश प्रयास ने

उसमें छेद कर दिया है। इसकी उच्चतम स्तर पर गहन जांच की जानी चाहिए ताकि यूपीएससी प्रवेश में धोखाधड़ी के ऐसे मापदण्ड विषय में न हो।

इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया: यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से लगभग पांच वर्ष पहले ₹व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)

के सूत्रों ने बताया कि, ₹यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ लगे आरोपों के बाद यूपीएससी गंभीर सवालों का सामना कर रहा है, जिन पर सिविल सेवा में प्रवेश पाने के लिए कथित तौर पर जाली पहचान पत्र तैयार करने का आरोप है।

कांवड़ मार्ग पर रिथिति दुकानों पर लगे नेमप्लेट, अमेठी सांसद बोले— इससे विदेशों में देश की छवि खराब हो रही है

संवाददाता | कांग्रेस दर्पण

अमेठी। यूपी सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग पर रिथिति दुकानों पर कर्मचारियों की नेमप्लेट लगाने के जारी किए गए आदेश पर अलग-अलग दलों के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पर ताजा बयान अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा का आया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले से देश की छवि विदेशों में खराब होती है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग भी विदेश जाते हैं अगर वहां की सरकारें भी ऐसा करें तो क्या होगा?

उन्होंने कहा कि मैं इस बात को सही नहीं मानता

हूं क्योंकि इससे विदेश में देश की छवि धूमिल होती है... मेरा मानना है कि यह नहीं करना चाहिए...। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर 'नेमप्लेट' लगाने के निर्देश पर कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा, ₹मैं इस बात को सही नहीं मानता हूं क्योंकि इससे विदेश में देश की छवि धूमिल होती है... मेरा मानना है कि यह नहीं करना चाहिए...।

बता दें कि भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी योगी सरकार के इस फैसले की निंदा की है और इसे वापस लेने की अपील की है।





ਕਾਂਕੜ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਾਬੋ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਨ: ‘ਪੁਨਾਵ ਹਾਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜ੍ਰਹਰ ਕਾ ਠੋਝ ਬਢਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਜ਼ਾ

आस मोहम्मद

मुज़फ्फरनगर। दिल्ली से 110 किमी दूर
मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर से हरिद्वार जाने वाले
दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग पर लक्ष्मी शुद्ध भोजनालय के
सामने 46 साल के अरविंद शर्मा एक ढाबा संचालक
गुलशाद से कांवड़ यात्रा के दौरान 10 से 12 दिन
ढाबा बंद रहने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अरविंद शर्मा
सेल्समैन हैं। वो इन ढाबों पर खाने का सामान सलाई
करते हैं। अरविंद बताते हैं कि उनके 6 ढाबा संचालक
ग्राहक मुस्लिम हैं। इनका ढाबा बंद रहने से उनके
कारोबार पर फर्क पड़ेगा। मांसाहारी ढाबे बंद रहते हैं तो
यह समझ में आता है, मगर शाकाहारी ढाबों पर यह
निर्णय सही नहीं है। यहां तो सभी मिलकर रहते हैं।

अरविंद शर्मा कहते हैं, 'मुस्लिम ढाबा बंद करवाने से क्या फायदा है? जो मासं बेच रहे हैं उनकी दुकान बंद कराना ठीक है। लेकिन जो शुद्ध शाकाहारी दाल-रेटी, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहे हैं, उनकी दुकानें क्यों बंद करवा रहे हैं? ये तो गलत बात है।'

शर्मी आगे कहते हैं, 'मुस्लिम होकर इन्होंने हिंदुओं का नाम रख लिया, चलो इसमें उनकी गलती है, उन्हें अपना नाम ही रखना चाहिए। इनको मुस्लिम नाम लिखना चाहिए और इसके आगे शुद्ध शाकाहारी लिखना चाहिए। फिर तो कई दिक्षित नहीं होनी चाहिए।'

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस समय ढाबों के नाम बदले जाने को लेकर काफी चर्चा है। कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर की सड़कों से तमाम कांवड़िये गुजरते हैं।

द्वाबों का हाल: द्वाबों में उदासी का माहौल है। लक्ष्मी शुद्ध भोजनालय द्वाबे के मालिक गुलशाद खान कहते हैं कि 'उनके 18 कर्मचारियों में से 17 हिंदू हैं। इसके अलावा दूध वाला, चिप्स वाला सेल्समैन, राशन वाला दुकानदार, सब्जी वाला सब हिंदू हैं। द्वाबा बंद रहेगा तो यह प्रभावित होंगे। नाम बदलकर रखने से ग्राहक नहीं आएंगे।' इससे समाज में बंटवारा हो रहा है।' कांवड़ मार्ग पर द्वाबों के नाम बदलने की कहानी सिर्फ मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं है बल्कि हरिद्वार तक जाने वाली हर सड़क की यही कहानी है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के अलावा दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसकी चिपेट में है। सैकड़ों द्वाबा संचालक, हजारों परिवार इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट संचालक, कट्टरवादी हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ नेता और इस पूरे मामले के सून्दराथ बघरा के एक आश्रम के संचालक यशवीर महाराज और उनके कुछ शिष्यों के अलावा कोई भी इस कार्यालय से ग्रव्ह नहीं है।

क जलावा काई भी इस कारबाइ से खुरा नहीं है। गैरतलब है कि यह सिर्फ तीन सालों से हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार सात साल से है। इस बार जितनी सक्रियता दिखाई गई है उत्तरी इससे पहले कभी नहीं रही है। एक बात समझ आती है कि हाल के चुनावों में दम हल्काको में दम की सिविलियांट दमकी तज़िद है।

मैं इस इलाके में हार का खाली स्थान है। इसका वजह है, कैसे पड़ी इसकी नीवः? मुजफ्फरनगर जनपद के शामली मार्ग पर यशवीर महाराज नामक एक व्यक्ति का आत्रम है। यशवीर महाराज की हिंदुत्वावादी छवि है। कोरोना काल के बाद जब पुनः कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई तो यशवीर महाराज ने मुजफ्फरनगर पुलिस को 50 से अधिक ढाबों की एक सूची सौंपी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि शुद्ध शाकाहारी का बोर्ड लगाए हुए इन हिंदू नाम वाले ढाबों के मालिक वास्तव में मुसलमान हैं और इस कारण कांवड़ यात्रा के समय कांवड़ ए



भ्रमित होते हैं। कांवड़ यात्रा के दैरान इन ढाबों को बंद होना चाहिए या इन्हें अपने ढाबों पर अपनी पहचान लिख देनी चाहिए, क्योंकि यहां खाना खाकर कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है।

पुलिस ने इसे गंभीरता नहीं लिया। इससे यशवीर महाराज नाराज हो गए और उन्होंने मुजफ्फरनगर में धरना दे दिया। लगातार आत्रमक भाषण होने लगे। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका के बीच यह चर्चा लखनऊ पहुंच गई। 2022 में ऐसे सभी ढाबों का सत्यापन कराया गया। ढाबा मालिक और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार की गई। 2023 में बिना लिखित आदेश के तमाम मुस्लिम मालिकों के ढाबों को बंद कर दिया गया। इस बार इससे भी आगे बढ़कर 230 किमी के कांवड़ मार्ग में हर प्रकार की दुकानों को चिह्नित कर उन्हें पहचान बताने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हिंदू ढाबा मालिकों से मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देने के लिए कहा गया है। मुसलमान ढाबा मालिकों को मुस्लिम नाम रखने अथवा ढाबा बंद रखने के आदेश हैं। इससे भी आगे यह है कि रोजमर्ग के सामान बेचने वाली दुकानों और फल-सब्जी की रेहड़ियों पर भी पहचान अंकित करने के लिए कहा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण ने इस इलाके के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ कर रख दिया है। इसे मसलमानों के बहिष्कार की महिम बताया जा रहा है।

मुसलमानों के बाह्यकार का मुहूर्ण बताया जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक और सौहार्द के लिए ख़तरनाक है यह मुहिमः पिछले कुछ सालों में स्थानीय प्रशासन ने बड़ी संख्या में इस मुस्लिम बहुल इलाके में कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए मुसलमानों का सहयोग लिया है। कांवड़ यात्रा की भव्यता लगातार बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक के खालापार इलाके में आता है जिसकी काफी चर्चा रहती है। इस मीनाक्षी चौक पर 10 सालों से लगातार कांवड़ियों के सेवा सत्कार के लिए शिविर लग रहे हैं। मुजफ्फरनगर की कई संस्था पैगाम-ए-इंसानियत, आवाज-ए-हक और सेकुलर फ़ंट इसी मीनाक्षी चौक पर हर साल भंडरों का आयोजन करती हैं और चिकित्सा शिविर लगाकर कांवड़ियों की सेवा करती हैं।

इसके अलावा शामली, सहारनपुर और खत्तौली में भी इसी तरह के शिविर लगते हैं, जिन्हें सिर्फ मुसलमान संचालित करते हैं। सैकड़ों मुसलमान नौजवान, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, वॉलंटियर के तौर पर प्रशासन का सहयोग करते हैं। मुजाफ्फरनगर के आसिफ राही, दिलशाद पहलवान, गौहर सिद्दीकी, महबूब अली, सत्तार मंसरी, उमर अहमद एडवोकेट

एक दशक से अधिक समय से ऐसा कर रहे हैं।

किदवई नगर के निवासी उमर अहमद एडवोकेट कहते हैं कि 'यह सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशें हैं।' उमर बताते हैं कि वो अपने हाथों से कांवड़ियों के पैर दबा चुके हैं, उनकी दर्वाई पट्टी की है, उन्हें फल और खाना खिलाया है, अब जैसा माहौल बनाया जा रहा है, उसमें मुसलमानों को खलनायक सिद्ध किया जा रहा है, अब उन्हें डर है कि ऐसी स्थिति में आग बुकी पहनकर या टोपी लगाकर निकल गए तो क्या होगा, 'अब तो बस एक आदेश बचा है कि जब तक कांवड़ यात्रा हो तब तक मुसलमान घर से बाहर न निकलें।'

मुसलमान और हिंदू समाज के बीच है रोज़गार का संगम: हरिद्वार जाने के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर मुख्य मार्ग हैं। इस मार्ग पर हजारों की संख्या में ढाबे हैं। जिन ढाबों के मालिक मुसलमान हैं, वहां तमाम कारसाज (कर्मचारी) हिंदू हैं और जिन ढाबों के मालिक हिंदू हैं वहां तमाम कारसाज मुस्लिम हैं। इस तरह लाखों लोग इस कारोबार से जुड़े हैं। आज ये सभी ढाबा संचालक तनाव में आ गए हैं। मुजफ्फरनगर और खट्टौली में कुछ ढाबा संचालकों को मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देने के लिए कह दिया है। ढाबा मालिक और उनके कर्मचारी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनका ढाबा बंद करने का फरमान आ गया है।

दिल्ली-पौड़ी मार्ग पर मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर कस्बे में लक्ष्मी शुद्ध भोजनालय पर काम करने वाले पवन कुमार बताते हैं कि वो पिछले 18 साल से यहां बतौर कुक काम करते हैं। उन्हें कभी उनके धर्म के कारण घेदभाव नहीं झेलना पड़ा। पवन के चार बच्चे हैं। पवन कांवड़ यात्रा का हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि इसमें अधिक ग्राहक आते हैं।

पवन कहते हैं, 'पहले पुलिस सिफरेट लिस्ट लगाने के लिए कहती थी। मेरे ढाबा का मालिक मुसलमान है और मुझे उनके साथ कभी कोई दिक्तात नहीं हुई। मैं 18 साल से एक ही ढाबे पर काम कर रहा हूँ, 15 दिन के लिए ढाबा बंद होता है तो मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं।' वे कहते हैं कि इन 15 दिनों पर हमारी साल भर की उमीदें टिकी रहती हैं।

पवन कुमार कहते हैं कि ढाबों पर नाम लिखवाना गलत है, क्या यह कहा जा सकता है कि हिंदू समाज के लोग तिलक लगाकर बैठें? 'हजारों हिंदू लोग मुसलमानों के व्यापार में जुड़े हुए हैं, इनके साथ उनकी रोटी भी छीन रहे हैं ये कौसी नीति है? हम मेहनत करके

कमाते हैं. बैंक का लोन भी चुकाना है. काम बंद होगा तो फिर कर्ज लेना पड़ेगा.'

'चुनाव हासे के बाद ज़हर का डोज बढ़ा रही है भाजपा': विवादों में रहने वाले जिस यशवीर महाराज की शिकायत को आधार बनाकर यह कर्तवाइ की जा रही है, वो 2018 से ऐसी मांग कर रहे थे। जून 2022 में उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने सालों तक उन्हें नजरंदाज किया तो फिर हाल ही में क्या हो गया?

लोग दावा कर रहे हैं कि इसका कारण शुद्ध राजनीति है. सहारनपुर मंडल से भाजपा का सफाया हो गया है. सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर लोकसभा में अब भाजपा का सांसद नहीं है. हरिद्वार से सटी हुई मंगलौर विधानसभा सीट भी अब कांग्रेस जीत चुकी है. मेरठ में भाजपा हारते-हारते बची है. 2013 के दंगे के बाद जो ऑक्सीजन भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके से मिली थी, वह समाप्त हो गई है. मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी नेता प्रमोद त्यागी कहते हैं कि 'भारतीय जनता पार्टी' को सामाजिक ताना—बाना मजबूत होता देखकर तकलीफ होती है. ये चुनाव हार गए, इनको लगता है कि नफरत के जहर का असर कुछ कम हो गया है. इसलिए डोज बढ़ा रहे हैं।'

एक और नेता राकेश शर्मा कहते हैं कि ‘मैं हिंदू हूँ। यह गलत है। हमारे समाज में मुसलमानों के प्रति सहानुभूति बन रही है। मुझे लगता है कि यहां के बड़े रेस्टोरेंट और द्वाबा मालिकों ने यह सजिश रची है ताकि वो अधिक लाभ कमा सकें। इसके लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया है।’

पुलिस प्रशासन ने क्या दी सफाई? : मुजफ्फरनगर
के एसएसपी अभिषेक सिंह कह रहे हैं कि ऐसा निर्णय
कानून व्यवस्था प्रभावित न हो इसलिए लिया गया है।
कांवड़ियों में किसी प्रकार कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।
कई बार कांवड़ियों के साथ खान- पान को लेकर
विवाद हो जाता है, नाम देखकर भी कांवड़िए कुछ
खरीदने को इच्छुक हैं तो पुलिस प्रशासन उसमें कोई
रुकावट नहीं है। नाम लिखने का यह निर्णय स्वेच्छा से
लिया गया है।

एसएसपी की इसी बात को सहारनपुर के डीआईजी ने भी देखा रखा है। उनका कहना है कि प्रशासन की प्राथमिकता सकुशल कांवड़ यात्रा संपत्र कराने की है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)



एनडीए के सहयोगी दलों ने कांवड़ मार्ग के खाद्य वित्रेताओं के लिए जारी निर्देशों का विरोध जताया

संवाददाता | कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखण्ड के अन्य जिलों में भी आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान भोजनालयों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने और उनके धर्म को स्पष्ट करने संबंधी निर्देश लागू होने के बाद सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दलों ने इस मुद्दे पर अपनी नागजगी जाहिर की है और इसे 'भेदभावपूर्ण' बताया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वह मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी किए गए परामर्श से सहमत नहीं हैं।

केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा, 'गरीबों के लिए काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें दलित, पिछड़े, ऊंची जातियां और मुस्लिम जैसे समाज के सभी वर्ग शामिल हैं। जब भी जाति या धर्म के नाम पर इस तरह का विभाजन होता है, तो मैं इसका समर्थन या प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र का कोई भी शिक्षित युवा, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से आता हो, ऐसी चीजों से प्रभावित होता है।' वहीं, मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) ने कहा कि वह केंद्र और राज्य सरकार, जिसका वह हिस्सा है, दोनों के समक्ष अपनी आपत्तियां उठाएंगी।

आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने अखबार से कहा, 'सबसे पहले हमारी पार्टी का रुख यह है कि अगर कोई ऐसा फैसला लिया जाता है जो लोगों के बड़े वर्ग को प्रभावित करता है, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात, इसका समय गलत है। खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार, हर भोजनालय को अपना नाम और अपने उत्पादों का विवरण प्रदर्शित करना होता है। अगर इसे (पुलिस के आदेश को) लागू करना है, तो इसे शाकाहारी और मांसाहारी में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसमें लाल या हेरे रंग के प्रतीक हों, जैसे कि खाद्य पैकेट पर होते हैं वहाँ हमारे देश में विभिन्न समुदायों के लोग हैं और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए।'

मिश्रा ने कहा, 'यूपी सरकार में हमारी हिस्सेदारी है और यूपी सरकार में हमारे मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। हम इस मुद्दे को केंद्र और राज्य में उठाएंगे।' आरएलडी ने गुरुवार को अखबार से कहा था कि उसे इस तरह के निर्देश की जरूरत नहीं लगती।

आरएलडी के उत्तर प्रदेश प्रमुख रामाशीष राय ने भी इस निर्देश को 'संविधान विरोधी कदम' बताया। राय ने कहा, 'सरकार को इसे बिना देंगे के वापस लेना चाहिए।'

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड), जो बिहार में भाजपा की सहयोगी है और जिसका समर्थन केंद्र में एनडीए सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, ने कहा कि यह निर्देश भारतीय समाज और एनडीए के लिए प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के खिलाफ है।

जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, 'बिहार में यूपी से भी बड़ी कांवड़ यात्रा होती है। वहाँ ऐसा कोई आदेश लागू नहीं है। यूपी में पुलिस द्वारा लगाए गए ये प्रतिबंध प्रधानमंत्री मोदी की 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की भावना का उल्लंघन है। अगर आदेश की समीक्षा की जाए या उसे वापस लिया जाए तो



अच्छा होगा।'

भाजपा ने निर्देश का बचाव किया: हालांकि, भाजपा ने आदेश का बचाव करते हुए कहा कि पिछले साल भी ऐसा ही था। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे और हाल ही में लोकसभा चुनाव हार गए, ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'मुजफ्फरनगर पुलिस का निर्देश कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी यही आदेश लागू थे। मेरठ के सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी इस आदेश का बचाव किया। उन्होंने कहा, 'यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वे जो खाना खा रहे हैं, उसे कौन बेच रहा है। देश भर में ऐसी कई रिपोर्टें आई हैं और हमने शादियों के दौरान एक खास समुदाय के लोगों द्वारा खाने को दूषित करने के अनगिनत वीडियो देखे हैं। मेरठ जोन के अतिरिक्त डीजीपी (ईडीजीपी) ध्रुव कांत ठाकुर ने कहा, 'खाने की दुकानों और सड़क किनारे टेलों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश पिछले साल भी लागू किया गया था। शर्ति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इन आदेशों का पालन किया जाना चाहिए।'

ठाकुर के अनुसार, निर्देश को सख्ती से लागू करने से पहले ही मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जैसे जिलों में भोजनालयों के मालिकों ने अपने मालिकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। ईडीजीपी ने कहा, 'इस तरह के कदम का उद्देश्य पूरी पारदर्शिता है, ताकि यात्रियों को कोई भ्रम न हो।'

मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपने आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया था: हालांकि, भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश की आलोचना के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने गुरुवार को एक संशोधित आदेश जारी किया था, जिसमें कहा

गया था कि यह स्वैच्छिक था।

नोटिस में कहा गया था, 'श्रावण के पवित्र महीने के दौरान कई लोग, विशेष रूप से कांवड़ये, कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं। अतीत में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ कांवड़ यात्रा मार्ग पर कुछ खाद्य वित्रेताओं ने अपनी दुकानों के नाम इस तरह से रखे थे कि यात्रियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई। ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने और भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए मार्ग के किनारे स्थित होटलों, ढाबों और अन्य खाद्य पदार्थ वित्रेताओं के मालिकों और कर्मचारियों से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी इच्छा से अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करें।' नोटिस में कहा गया है, 'इस आदेश का उद्देश्य कोई धार्मिक मत भेद पैदा करना नहीं है, बल्कि केवल भक्तों की सुविधा के लिए है। इस तरह के आदेश पहले भी प्रचलित रहे हैं।'

वहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा ने शुक्रवार को इस परामर्श को तुरंत वापस लेने और इसके पीछे के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून के तहत सभी समान हैं।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में टेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है।'

उन्होंने कहा कि समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर

से कांग्रेस संसद इमरान मसूद ने कहा कि इस तरह के निर्देश से केवल नफरत फैलेगी और इसके पीछे के अधिकारियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि इस तरह के निर्देश शहर में फिर से हिंसा ला सकते हैं, जहाँ 2013 के दंगों से पहले सांप्रदायिक सौहार्द का इतिहास रहा है। वहीं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जिस तरह दलितों को कभी छुआछूत का शिकार होना पड़ता था, उसी तरह मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने की कोशिश की जा रही है। इस कदम के दूरगामी परिणामों के प्रति चेतावनी देते हुए मदनी ने कहा, 'इससे मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने वाली ताकतों को बल मिलेगा और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को स्थिति का फायदा उठाने का अवसर मिलेगा।' उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा गुजरती है, वहाँ मुसलमानों ने हमेशा कांवड़यों की मान्यताओं और प्रथाओं का सम्मान किया है और उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है।' मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भक्तों के 'सम्मान' के लिए इस वर्ष राज्य में कांवड़ यात्रा के मार्गों पर खुले में मांस की बिन्दी और खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

वहीं, उत्तराखण्ड के हरिद्वार में भी पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क किनारे टेलों सहित खाने-पीने की दुकानों को अपने मालिक का नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा है। इसके अलावा दिशा-निर्देशों में होटलों और ढाबों में मांस, अंडे, लहसुन और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना, शराब और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना, खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट को प्रमुखता से प्रदर्शित करना और भुगतान के लिए ऑपरेटर के नाम का क्यूआर कोड सुनिश्चित करना शामिल है।



सांप्रदायिकता, धूवीकरण और भ्रष्टाचार के नायकों के बल पर झारखंड में चुनाव जीतना चाहती है भाजपा: बंधु तिर्की

संचाददाता | कांग्रेस दर्पण

रांची। पूर्व मंत्री, झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब सांप्रदायिकता, धूवीकरण और भ्रष्टाचार के नायक बन चुके अपने तीन-चार प्रमुख नेताओं के बल पर झारखंड में विधानसभा चुनाव को जीतना चाहती है। श्री तिर्की ने कहा कि ऐसा मंसूबा पालनेवाले भाजपा नेताओं को अब यह समझना चाहिए

कि झारखंड वैसी जयीन है, जहां सांप्रदायिक सद्व्याव और आपस में एकजुटता कूट-कूट कर भरा है और यहां भाजपा नेताओं की दाल नहीं गलने वाली चाहे वह अमित शाह हों या फिर शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा सरमा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाबूलाल मरांडी जैसे भाजपाई नेता। आज रांची में भाजपा झारखंड प्रदेश की विस्तृत कार्यसमिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दिये गये वक्तव्य पर अपनी



केवल सांप्रदायिकता और धूवीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ही चुनाव जीतना चाहते हैं।

बुलडोजर तंत्र में झुग्गी-झोपड़ी गालों के साथ अन्याय नहीं होने देगी दिल्ली कांग्रेस !



संचाददाता | कांग्रेस दर्पण

आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री Devender Yadav जी ने देया बस्ती और तुलसी नगर झुग्गियों को तोड़ने के नोटिस से परेशान निवासियों से जाकर मूलाकात की। अध्यक्ष जी ने सभी को हिम्मत बंधाते हुए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस की सरकार ने ज़रूरतमंदों के सर पर छत दी है, घर बसाये हैं और भाजपा और आप ने सिर्फ बसे-बसाये घरों को

तोड़ा है। दिल्ली कांग्रेस झुग्गीवासियों के साथ उनकी ढाल बनकर मज़बूती से खड़ी है। पूर्व मंत्री विजय लोचर जी, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज जी, पूर्व विधायक राजेश जैन जी, पूर्व AICC सेक्रेटरी तरुण कुमार जी, चांदनी चौक जिला अध्यक्ष जावेद मिर्जा जी, दिल्ली कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल वहिद कुरैशी जी, पूर्व यार्ड प्रेरणा सिंह जी, संजय शर्मा जी, पार्श्व उम्मीदवार पंकज प्रहलाद सिंह राना जी मौजूद रहे।

विधानसभा स्तरीय बैठक

संचाददाता | कांग्रेस दर्पण

आज झारखंड की राजधानी राँची में राँची महानगर की विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में राँची, हटिया और कॉके विधानसभा के प्रखण्ड अध्यक्षों का सत्यापन और कार्यकर्ताओं से संचाद स्थापित कर संगठन हित में सुझाव लिए गए।

बैठक की अध्यक्षता महानगर जिलाध्यक्ष श्री गौरव सिंह द्वारा की गई, बैठक में राष्ट्रीय समन्वयक श्री कमल दीप सिंह बिष्ट द्वारा कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई, साथ ही कार्यकर्ताओं को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश सिन्हा सन्नी का मार्गदर्शन मिला।

बैठक में पूर्व युवा कांग्रेस नेता श्री प्रिंस बट, जिला प्रभारी श्री आफताब आलम, प्रदेश

प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री तिर्की ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रांची दौरे के दौरान यह भरोसा था कि वे केंद्र पर बकाया झारखण्ड के उस 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये को झारखंड को देने के मामले में कोई ऐसा वक्तव्य देंगे, जिससे यहां एक सकारात्मक वातावरण पैदा होगा और झारखंड के लोगों को यह विश्वास होगा कि भारतीय जनता पार्टी हाल के लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद अब अपनी गलती को सुधारना चाहती है, लेकिन श्री शाह ने जैसा भाषण दिया है उससे यह स्पष्ट है कि भाजपाई नेता केवल और



दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री खर्गीय शीला दीक्षित जी की पुण्यतिथि पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पृष्ठांजलि कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री Devender Yadav जी, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी, पूर्व मंत्री नरेन्द्र नाथ जी, पूर्व मंत्री मंगत राम सिंहल जी, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज जी, पूर्व विधायक अमरीश गौतम जी, पूर्व विधायक सुरेन्द्र कुमार जी, पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पार्टी पदाधिकारी-कार्यकर्तागण ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आधुनिक दिल्ली के नव-निर्माण के लिए श्रद्धेय शीला जी और उनके योगदान सदैव स्मरण किए जाएंगे।

कुलदीप इंदौरा जी का स्वागत

संचाददाता | कांग्रेस दर्पण

राजस्थान की गंगानगर लोकसभा से सांसद, एआईसीसी सचिव और मध्यप्रदेश के सहप्रभारी कुलदीप इंदौरा जी का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वागत किया गया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश कांग्रेस

के प्रभारी महासचिव श्री जितेंद्र सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी एवं राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह जी सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण मुख्य रूप से उपस्थित रहे।





भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि के यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन

संचारदाता | कांग्रेस दर्पण

आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून युवा कांग्रेस के महानगर कार्यकारी अध्यक्ष मोहित महता (मोनी) के नेतृत्व में भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि के यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

देहरादून युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मोहित मेहता (मोनी) ने दिल्ली में बनाए जा रहे केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक स्वरूप के शिलान्यास का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बनाए जा रहे केदारनाथ मंदिर के स्वरूप को लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसके लिए जनता से सार्वजनिक माफी मांगें।

युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि केदारनाथ मंदिर से शीला ले जाकर दिल्ली में फाउंडेशन स्टोन रखा गया जो कि हमारे धर्म, आध्यात्मिक मान्यताओं को व्यावसायिक मार्ग पर ले जाने का प्रयास है। भाजपा के पास अब भी उत्तराखण्ड की आस्था को बचाने के लिए बक्त बचा है। पुणे, दिल्ली ले जाई गई शिला को वापस लाना चाहिए।

प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भण्डारी ने कहा कि कोई भी मंदिर बनाएं, लेकिन केदारनाथ की प्रतिकृति नहीं बननी चाहिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं और हम उस संस्था से भी निवेदन कर रहे हैं कि यह हमारी आस्था

फलानाथ द्वायाओ
बुद्धि शुद्धि यज्ञ
हमारी आस्था से खिलाफ बढ़ कर
आयोजक : उत्तराखण्ड युवा कांग्रेस



का प्रश्न है। इसलिए दिल्ली में केदारनाथ की प्रतिकृति नहीं बनाई जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष (महानगर युवा कांग्रेस प्रभारी) नवीन रमेला ने कहा कि उत्तराखण्ड केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत जो लगभग 228 किलो सोना चौरी हो गया। वह सोना कहां गया? पता नहीं चला। उसके बावजूद मुख्यमंत्री शिला लेकर

दिल्ली कैसे चले गए। ऐसे में क्या पुरातत्व विभाग भाजपा सरकार पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में केवल चार धाम हैं। पांचवा धाम नहीं हो सकता है। लेकिन भाजपा सरकार धाम को व्यापार का केंद्र बना रही है।

कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री करन

माहरा जी, श्री प्रीतम सिंह जी पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री गणेश गोदियाल जी, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मधुरादत जोशी, प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत जी संग सभी नेतागण और कार्यकर्ताजन मौजूद रहे।

कांग्रेस युवाओं के मजबूत कंधों के सहारे विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी

संचारदाता | कांग्रेस दर्पण

हाऊसिंग कॉलोनी स्थित कांग्रेस कार्यालय धनबाद में झारखण्ड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज जी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर करुण नन्दन पासवान, प्रदेश सचिव सह प्रभारी विक्री कुमार जी की उपस्थिति में धनबाद ज़िला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव के नेतृत्व में धनबाद विधानसभा की कार्यकारणी की बैठक संपन्न हुई। जिसमें युवा कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कड़ी निर्णय ली है। विधानसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस युवाओं के मजबूत कंधों के सहारे विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में आज धनबाद कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने यूथ जोड़ों बूथ जोड़ों वा डोर टू डोर, कैपेन करने और जल्द से जल्द हर बूथ पर जाकर युवाओं को जोड़ने का टास्क दिए। ₹युथ जोड़ों बूथ जोड़ों वा ₹डोर टू डोर को जिले भर के बेरोजगार युवाओं को इस मुहिम से जोड़ने का काम रही है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री रोजगार जैसे विषयों से युवाओं का ध्यान भटकाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। साथ ही युवाओं के साथ छल किया है। ऐसे में युवा बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत युवा कांग्रेस ने हर एक बूथ पे पांच सदस्य को जोड़ने का टारगेट रखी गई है।

इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित झारखण्ड



प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर करुण नन्दन पासवान, प्रदेश सचिव, जिला सहप्रभारी विक्री कुमार, धनबाद ज़िला महासचिव बब्लू दास, जिला महासचिव विक्री कुमार, सोनू यादव, कैलाश दास, विधानसभा अध्यक्ष दीपक यादव कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे।